"पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड"

12 नवंबर, 2012

Power Finance Corporation Ltd.
A Govt. of India Undertaking

MOTILAL OSWAL

CHORUSCALL®

विश्लेषक : श्री उमंग शाह

प्रबंधन : श्री सतनाम सिंह,
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

मॉडरेटर : देवियो और सज्जनो, नमस्कार। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज लिमिटेड द्वारा आयोजित वित्त वर्ष 2013 की दूसरी तिमाही की रिजल्ट कॉन्फ्रेंस कॉल के अवसर पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। इस कॉन्फ्रेंस कॉल की अवधि के लिए एक अनुस्मारक के रूप में सभी प्रतिभागियों की लाइनें केवल सुनने के प्रयोजन (लिसेन ओनली मोड में) से रहेंगी और आज के प्रजेंटेशन की समाप्ति पर आप सभी को प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर आप अपने टच टोन टेलीफोन पर "*" तत्पश्चात "0" दबाकर किसी ऑपरेटर को संकेत कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि इस कॉन्फ्रेंस की कार्यवाही को रिकॉड किया जा रहा है। अब मैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज लिमिटेड के श्री उमंग शाह को कॉन्फ्रेंस की आगे की कार्यवाही के संचालन का दायित्व सौंपना चाहूंगा। धन्यवाद महोदय।

उमंग शाह : धन्यवाद मेलिसा।

देवियो और सज्जनो सुप्रभात। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की ओर से मैं वित्त वर्ष 2013 की दूसरी तिमाही के परिणामों पर चर्चा करने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अर्जन कॉल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच श्री सतनाम सिंह, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड मौजूद हैं। अधिक औपचारिकताओं के बिना अब मैं आगे की कार्यवाही के संचालन का दायित्व श्री सतनाम सिंह जी को सौंपना चाहूंगा जो विगत तिमाही के दौरान कंपनी के निष्पादन के बारे में हमें संक्षिप्त जानकारी देंगे और तत्पश्चात एक प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया जाएगा। आइए और संचालन का दायित्व संभालिए।

सतनाम सिंह : सभी को सुप्रभात। मेरा विचार है कि तिमाही परिणामों के बारे में चर्चा करने से पहले मुझे आपको पांच अथवा छः महत्वपूर्ण बातों की जानकारी

देनी चाहिए, जो मैं आपके साथ इस अवसर पर साझा करना चाहता हूं, जिनके बारे में जानकर आप सभी को राहत महसूस होगी कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले यह कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय पुनर्गठन योजना के माध्यम से इस क्षेत्र की व्यवहार्यता का समाधान तेजी से किया जा रहा है और वर्तमान में राज्य इसके कार्यान्वयन से पहले अपने - अपने विधानमण्डलों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। पुनर्गठित एपीडीआरपी योजना, जिसका उद्देश्य संपूर्ण देश के 1400 कस्बो में एटी एवं सी हानियों को कम करना है, का भी कार्यान्वयन तेजी से किया जा रहा है। अब तक लगभग 215 कस्बों को एकीकृत किया गया है और यहां तक कि प्रणाली को उन्नत किए बिना चार राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में प्रशासनिक उपायों के जरिए हानि स्तर को 1% से 10% के स्तर तक लाया गया है।

इसके अलावा राज्य विद्युत नियामकों से हर वर्ष टैरिफ में वृद्धि करने विषयक अपीलकर्ताओं की व्यवस्था सुचारु रूप से कार्य कर रही है चाहे राज्यों ने टैरिफ याचिका दायर की हो अथवा नहीं। लगभग 27 राज्यों ने वित्त वर्ष 2012-13 के लिए टैरिफ आदेश पहले ही जारी कर दिए हैं। इनके अंतर्गत टैरिफ में 0-37% तक की वृद्धि की गई है। इसके अलावा ऐसे क्षेत्र जिन्हें पुनर्गठित एपीडीआरपी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, के लिए सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत निधि नामक एक अन्य योजना पहले ही अनुमोदित कर दी है जो हानि स्तर में सुधार के लिए एक

सब्सिडी आधारित योजना है।

इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय भी सहयोग प्रदान कर रहा है, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि ईंधन की आपूर्ति के लिए कोल इण्डिया लिमिटेड और विकासकर्ताओं के बीच करारों पर हस्ताक्षर हो गए हैं।

एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संधिकाल के दौरान वित्तीय व्यवस्था कैसे की जाए, इस संबंध में बकाया नकदी अंतराल को पूरा करने के लिए पीएफसी और आरईसी ने निश्चय किया है, जो इन एफआरपी के कार्यान्वयन के पश्चात वितरण कंपनियों के पास होगी।

इस प्रकार यदि आप इन सभी प्रयासों को एक साथ देखेंगे तो यही जवाब सामने आएगा कि इस क्षेत्र की व्यवहार्यता और जीवन क्षमता का समाधान तेजी से किया जा रहा है। अब इस बात पर चर्चा की जाए कि इस पहल का परिणाम क्या होने वाला है? इसका परिणाम यह है कि एनपीए के स्तर न्यूनतम रहेंगे। ज्यादातर पणधारक यह उम्मीद कर रहे हैं कि इन मुद्दों के कारण आगे बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र में बहुत से एनपीए मौजूद होंगे, जो भलीभांति परिचित हैं परंतु यदि आप इन सभी प्रयासों पर नजर डालेंगे, तो मेरा मानना है कि जहां तक गैर निष्पादन वाली परिसंपत्तियों का संबंध है तो उन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा; हालांकि हमारी दूसरी तिमाही के परिणामों में मुझे आपको सूचित करते हुए हर्ष है कि एनपीए में कोई भी नया खाता नहीं जोड़ा गया है।

अन्य संदेश जो मैं आप सभी को देना चाहता हूं, यह है कि आगे चलकर ऋण लेने की लागत में कमी होने की संभावना है। वस्तुत: हमने विदेशी मुद्रा ऋण लिया हुआ है, हम वर्तमान में विदेशी मुद्रा में अन्य ऋण लेने

के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। हमने अभी हाल ही में एनटीएम कार्यक्रम के लिए रोड शो पूरे किए हैं, जिसमें पांच वर्ष और उससे अधिक अवधि के दीर्घकालीन ऋण शामिल हैं और हम आगामी सप्ताह में कभी भी इनकी कीमत निर्धारित करने वाले हैं। भारत सरकार ने कर मुक्त बॉण्डों के लिए पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे मामले में हमें 5000 करोड़ रूपए की राशि दी गई है। यदि आप इन सभी इश्यू की ऋण लागत देखेंगे तो यह निर्धारित लागत की तुलना में काफी कम है। इस प्रकार यह ट्रेंड आगे भी जारी रहने वाला है और यदि भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरें कम करने का निश्चय करता है, तो अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर स्थानीय बाजार से भी निधियां उपलब्ध हो सकती हैं, इस प्रकार इन सभी घटकों के परिणामस्वरूप आगे चलकर ऋण लेने की लागत कम होने की संभावना है।

तीसरा संदेश जो मैं आपको देना चाहता हूं, यह है कि हमारे नए व्यापार क्षेत्रों की प्रगति भलीभांति हो रही है। हमारी परामर्श सेवा प्रदान करने वाली सहायक कंपनी को चार स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। हमारी कंपनी ने पूंजी सलाहकार सेवाओं से प्रचालन के महज एक वर्ष पश्चात ही एक करोड़ रूपए से अधिक की आय सृजित की है। हमारे हरित ऊर्जा प्रयास, पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को अभी एनबीएफसी दर्जा प्राप्त हुआ है और यह कंपनी 1,000 करोड़ रूपए की परिसंपत्तियों के साथ अपना प्रचालन शुरू करेगी। यह राशि पीएफसी द्वारा पीएफसी जीईएल को हस्तांतरित की जाएगी। अभी हाल ही में हमने वैश्विक स्तर

पर अपना प्रचालन प्रारंभ किया है। हमने अभी हाल ही में वीडियो कॉन को मोजाम्बिक ऑयल फील्ड, गैस फील्ड के लिए 2200 करोड़ रूपए का ऋण इस प्रावधान के साथ स्वीकृत किया है कि वह यहां से उत्पादित गैस भारत को उपलब्ध कराएगी, जिससे भारत में विद्युत उत्पादन सुकर बनेगा।

हम शीघ्र ही अपने निजी इक्विटी प्रयास के लिए टाटा कैपिटल के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी निबंधन और शर्तें लगभग अंतिम चरण में हैं। हो सकता है कि हम आगामी तीन माह में करार पर हस्ताक्षर करने में सफल हो जाएं। अगले संदेश जो मैं आपको देना चाहता हूं यह है कि हमें इस बात पर नजर रखना है कि अन्य संस्थान क्या कर रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक हमसे क्या करने की अपेक्षा करता है; हमने मानक परिसंपत्तियों का प्रावधान करने का निश्चय किया है। आवश्यकता 0.25% थी। यह स्वैच्छिक आवश्यकता है, परंतु हम ऐसा पहले नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे पास खाता बही में लगभग 1% के समतुल्य बफर स्टॉक ऐसी किसी आकस्मिकता को पूरा करने के लिए अशोध्य और संदेहास्पद कर्ज के लिए आरक्षित निधि के रूप में था। हालांकि, चालू वर्ष के दौरान लाभप्रदता में काफी सुधार हुआ है, फिर भी हमारा मानना है कि यह प्रावधान इस वर्ष से प्रारंभ कर आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए करना उचित होगा। इस वर्ष हम 0.08% का प्रावधान करेंगे तत्पश्चात वित्त वर्ष 13-14 के लिए 0.08% और फिर वित्त वर्ष 14-15 के लिए 0.09% का प्रावधान किया जाएगा

जो ऐसी किसी आवश्यकता होने पर हमें अतिरिक्त रूप से सहायक होगा।

अंतिम संदेश जो मैं आपको देना चाहता हूं यह है कि हमने तिमाही के साथ साथ पहली छमाही के दौरान उच्च लाभप्रदता और उन्नत विस्तार तथा परिसंपत्तियों में वृद्धि प्रदर्शित की है।

अब मैं उस बात पर चर्चा करूंगा जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं अपनी बात ऋण परिसंपत्तियों से शुरू करूंगा। तिमाही के दौरान हमारी ऋण परिसंपत्तियों में 28% की वृद्धि हुई है और यह 1110,421 करोड़ रूपए से बढ़कर 140,189 करोड़ रूपए हो गई है। ये पहली छमाही के आंकड़े हैं। यह प्राथमिक रूप से वर्ष की शुरुआत में 160,529 करोड़ रूपए तक के उत्कृष्ट स्वीकृति के परिणामस्वरूप संभव हो सका है और ऐसे ऋणों का संवितरण किया गया है जो पहले से प्रक्रियाधीन थे। यदि उन क्षेत्रों का उल्लेख किया जाए जहां उच्च स्तर का संवितरण किया गया है, तो इसमें निजी क्षेत्र की ऐसे परियोजनाएं जो प्रगति पर हैं, के अलावा महाराष्ट्र की कोराडी परियोजना, आंध्र प्रदेश की कृष्णापट्टनम परियोजना, तमिलनाडु की एन्नोर परियोजना और राजस्थान की कालीसिंध परियोजना प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। ऋण परिसंपत्ति में वृद्धि के परिणामस्वरूप तिमाही के दौरान हमारी कुल आय 3145 करोड़ रूपए से बढ़कर 4191 करोड़ रूपए हो गई है जो 33% की वृद्धि दर्शाती है और छमाही आधार पर इसमें 34% की वृद्धि हुई है क्योंकि 6069 करोड़ रूपए से बढ़कर 8136 करोड़ रूपए हो गई है।

तिमाही के दौरान संगत रूप से हमारी निवल आय में भी वृद्धि हुई है और यह 33% की वृद्धि के साथ 1079 करोड़ रूपए से बढ़कर 1475 करोड़ रूपए हो गई है और छमाही के दौरान यह 2069 करोड़ से बढ़कर 2869 करोड़ हो गई है जो कि 39% अधिक है। तिमाही के लिए कर पश्चात लाभ 147% अधिक है। यह 419 करोड़ रूपए से बढ़कर 1036 करोड़ रूपए हो गया है और छमाही के लिए 1106 करोड़ रूपए से बढ़कर 2008 करोड़ रूपए हो गया है, इस प्रकार इसमें 82% की वृद्धि हुई है।

अब आप यह कह सकते हैं कि इसमें अच्छी खासी वृद्धि हुई है। हां, अत: मैं इस बात से सहमत हूं कि हमने कर पश्चात लाभ की तुलना में इसकी गणना की है जो इस विशेष मामले में असाधारण मद के समायोजन के पश्चात की गई है। गत वर्ष हम दूसरी तिमाही तक विदेशी मुद्रा की हानि की बुकिंग के लिए मार्क-टू-मार्केट प्रणाली का अनुपालन करते रहे; हालांकि तीसरी तिमाही जब भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा हानि के मोचन की तारीख तक मोचन के लिए विकल्प दिया और फिर आनुपातिक संरचना के आधार पर किसी विशेष वित्त वर्ष में प्रभारित करने का विकल्प दिया, के दौरान हमने उस विकल्प का चयन किया था। यदि वह विशेष समायोजन कर पश्चात लाभप्रदता की तुलना में किया जाता है, तो यह हमारी परिसंपत्ति वृद्धि के अनुरूप है जिसमें 33% की वृद्धि हुई है और तिमाही दर तिमाही आधार पर यह 812 करोड़ रूपए से बढ़कर 1084 करोड़ रूपए हो गई है और छमाही आधार पर इसमें 37% की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार यह 1537 करोड़ रूपए

से बढ़कर 2113 करोड़ हो गई।

अब मुझे आप लोगों को निधियों की स्वीकृति और लागत के संबंध में जानकारी देनी चाहिए। तिमाही के दौरान हमारी स्वीकृतियों में सुधार हुआ है और यह 11.29% से बढ़कर 11.98% हो गई है। इसी प्रकार छमाही के लिए इसमें 11.19% की तुलना में 11.84% की वृद्धि हुई है जो क्रमश: तिमाही और छमाही के लिए 68 बीपीएस और 66 बीपीएस अधिक है। तिमाही के लिए निधियों की लागत 9.08% बढ़कर 9.24% और छमाही के लिए 8.93% से बढ़कर 9.16% हो गई है। तदनुसार तिमाही के लिए विस्तार 53 बीपीएस अर्थात 2.21% से बढ़कर 2.74% हो गया है और छमाही के लिए 42 बीपीएस अर्थात 2.26% से बढ़कर 2.68% हो गया है। निवल ब्याज मार्जिन 3.97% से बढ़कर 4.28% हो गया है अर्थात तिमाही के लिए 31 बीपीएस और छमाही के लिए 32 बीपीएस के साथ 3.91% से बढ़कर 4.32% हो गया है।

मुझे विश्वास है कि आप सभी ने पहले भी इस प्रकार के परिवर्तन के औचित्य पर जानकारी देते हुए मुझे अवश्य सुना होगा, परंतु मैं एक बार इस बात को पुन: दोहराना चाहूंगा। हमारे पास वर्ष दर वर्ष ऐसी परिसंपत्तियों और देनदारियों की कीमत पुन: निर्धारित करने की एक प्रणाली मौजूद है; हालांकि परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्य निर्धारण एक वर्ष में केवल चार बार अर्थात प्रत्येक तिमाही में एक बार किया जाता है जब कि देनदारियों का पुनर्मूल्य निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज

मूल्य में वृद्धि होने पर किया जाता है और अंत में, डेढ़ वर्ष बाद किया जाता है। जैसा हम सब जानते हैं कि आरबीआई अपनी ब्याज दरों में कभी भी, विशेष रूप से जनवरी 2012 से पहले अक्सर वृद्धि करता रहा है। अत: ऐसी स्थिति में हमारी देनदारियों का पुनर्मूल्य निर्धारण तब तक किया गया जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की गई; हालांकि हम उस वृद्धि को अपने ऋणकर्ताओं के लिए लागू नहीं कर सके क्योंकि देनदारियों के मूल्य में वृद्धि को ग्राहकों पर लागू करने की संरचना केवल तिमाही वृद्धि के माध्यम से ही संभव थी। इस प्रकार इस मामले में हमेशा एक अंतराल बना रहा और इसके परिणामस्वरूप हमारे एनआईएम और विस्तार में 20-30 बीपीएस की कमी हो गई, परंतु जब से रिजर्व बैंक ने कभी भी अपनी ब्याज दरों में वृद्धि की प्रक्रिया में रोक लगाई है, हमारा एनआईएम और विस्तार पुन: अपने सामान्य स्तर पर पहुंच गया है और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जैसा मैंने आप सभी को पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ऋण लेने की लागत में कमी होने की संभावना है और विदेशी मुद्रा ऋण के साथ साथ कर मुक्त बॉण्ड में भविष्य में और सुधार होगा, बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक भी ब्याज दरों में को कम करने का निश्चय करे जिसके परिणामस्वरूप सभी बैंक और वित्तीय संस्थान भी ब्याज दरों को कम करने पर विचार करेंगे।

तिमाही के दौरान अन्य आंकड़े, हमारी स्वीकृतियों में 101% की वृद्धि हुई और यह 15,163 करोड़ रूपए से बढ़कर 30,550 करोड़ रूपए हो गई। इसी प्रकार छमाही के लिए यह 28398 करोड़ रूपए से बढ़कर

41732 करोड़ रूपए हो गई अर्थात इसमें 47% की वृद्धि दर्ज की गई। संवितरण में 19% की वृद्धि हुई। तिमाही के दौरान यह 8135 करोड़ रूपए से बढ़कर 9672 करोड़ रूपए हो गया। इसी प्रकार छमाही के लिए इसमें 23% की वृद्धि हुई और यह 14234 करोड़ रूपए से बढ़कर 17555 करोड़ रूपए हो गया। चूंकि दूसरी तिमाही की समाप्ति पर हमारे पास 168,000 करोड़ रूपए की स्वीकृतियां बकाया हैं, अत: हमें पूर्ण विश्वास है कि हम परिसंपत्ति वृद्धि को आगे भी इसी तरह बनाए रखने में सक्षम होंगे।

अब हम पूंजी पर्याप्तता अनुपात की बात करेंगे। पूंजी पर्याप्तता अनुपात, पहली तिमाही के अंत में 18.55% था, कम होकर 17.69% हो गया है क्योंकि हमारी परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है। शुरुआत में ही मैंने उल्लेख किया था कि इस तिमाही के दौरान एनपीए की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तिमाही के अंत में ऋण परिसंपत्ति के प्रतिशत के रूप में हमारा सकल एनपीए 0.97% रहा और निवल एनपीए 0.86% रहा। वे पहली तिमाही की तुलना में कम रहे जो क्रमश: 1.02% और 0.91% हैं। यह केवल इसलिए हुआ क्योंकि ऋण परिसंपत्ति बही में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। संधिकालीन वित्त पोषण जिसके बारे में हमने चर्चा की कि वह 19630 करोड़ रूपए है, 6 राज्यों अर्थात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें यद्यपि आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है, परंतु उन्होंने अभी तक किसी भी संधिकालीन वित्त पोषण के लिए अनुरोध नहीं किया है।

इस प्रकार के ऋण के लिए हमारे द्वारा स्वीकृति अवधि 10 वर्ष है, जिसमें तीन वर्ष का अधिकतम अधिस्थगन काल है। निश्चित रूप से हम यह ऋण राज्य सरकार की गारंटी के बिना प्रदान करने के लिए सहमत नहीं हैं और इस शर्त के अध्यधीन ही यह ऋण दिया जाएगा जब राज्य सुधार संबंधी शर्तों पर कार्रवाई शुरू करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करेंगे क्योंकि यह वितरण कंपनियों के राजस्व में वृद्धि के लिए अनिवार्य है।

अब तक हमने इस मद में केवल 5500 करोड़ रूपए का ही संवितरण किया है परंतु सितंबर तक यह लगभग 2100 करोड़ रूपए ही था जैसा कि मैंने आप से पहले ही जिक्र किया है कि विदेशी मुद्रा ऋण के रूप में हमने 250 मिलियन डॉलर की राशि तीन वर्ष के लिखित करार पर 31 अगस्त को आहरित की है। हमने अपने एमटीएन कार्यक्रम के लिए रोड शो पूरे कर लिए हैं, जिसके लिए हम इसके मूल्य का निर्धारण हो सकता है, अगले सप्ताह में करें और हमें अगले तीन वर्ष के ईसीबी ऋण के लिए मूल्य दरें प्राप्त हो गई हैं। यह बहुत ही आकर्षक होने वाला है और हम शीघ्र ही मर्चेंट बैंकर को संविदाओं का अधिनिर्णय करेंगे वित्त मंत्रालय ने कर मुक्त बॉण्डों की अधिसूचना जारी की है। हम ऐसे कर मुक्त बॉण्ड लांच करने की तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है एक माह के भीतर ऐसे बॉण्ड जारी किए जाएं अब तक 40,000 करोड़ रूपए की हमारी निधि आवश्यकताओं की तुलना में हमने पहले ही 17721 करोड़ रूपए जुटा लिए हैं और कर मुक्त बॉण्ड तथा विदेशी मुद्रा ऋण, जिसके

बारे में मैंने अभी आपके साथ चर्चा की है, पर भी हम काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जहां तक संसाधन जुटाने का प्रश्न है तो इस संबंध में हमें काफी राहत है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में आहरित न की गई प्रतिबद्धताओं के लिए पूंजी आवश्यकता का प्रावधान किया है। अब हमने भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय तथा मंत्रिमण्डल सचिव के ध्यान में लाया है कि इस प्रकार की संरचना विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए सही नहीं है क्योंकि हमें ऐसे ऋण स्वीकृत करने पड़ते हैं जो लंबे समय तक अप्रयुक्त बने रहते हैं क्योंकि विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण के संवितरण में तीन से चार वर्ष का समय लगता है, अत: इनके मामले में कुछ न कुछ प्रतिबद्धता हमेशा शेष रहेगी। अवसंरचना वित्तीय कंपनियों के मामले में इन्हें इस मद में अतिरिक्त पूंजी सृजित करनी पड़ती है और इस कारण उनकी लैंडिंग लागत बढ़ जाती है, इसके अलावा संस्थानों को अपेक्षाकृत अधिक पूंजी रखनी पड़ती है जो उन संस्थानों को सामान्यत: आवश्यक होती है। इस प्रकार हमें यह देखना है कि आरबीआई ने मार्च 2013 तक तो इस मद में हमें छूट प्रदान की है, परंतु हमें उम्मीद है कि आरबीआई आने वाले समय में भी यह छूट प्रदान करेगा।

हमारी सहायक कंपनियां बेहतर निष्पादन कर रही हैं। मैंने आपके समक्ष उनके आंकड़े पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं। पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की स्थापना के पश्चात नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार की तरफ हम अधिक

ध्यान दे रहे हैं, मुझे आपको सूचित करते हुए हर्ष है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को लचीली शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आगे आए हैं, परंतु वर्तमान में ऐसे सभी प्रस्तावों पर बातचीत की जा रही है और जैसे ही उन पर कोई निर्णय लिया जाता है तो हम आप सभी को सूचित करेंगे कि पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जैसी एक अलग केन्द्रित कंपनी के रूप में ऋण लेने का क्या लाभ हुआ।

अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के संबंध में जैसा मैंने आप सभी को पहले ही सूचित किया है कि हमने ऐसी चार परियोजनाओं का अधिनिर्णय किया है। जहां तक पूर्व अर्हताओं के अनुपालन का संबंध है, तो हमने तीन अर्थात उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और चेय्यूर के लिए तैयारी कर ली है परंतु हम उनके संबंध में आगामी कार्रवाई करने से पहले विद्युत मंत्रालय से दस्तावेजों की प्रतीक्षा करेंगे। तीन और नई अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के संबंध में काफी प्रगति की गई है। इनमें से दो अतिरिक्त यूएमपीपी उड़ीसा में और एक झारखण्ड में स्थापित की जानी है। इसी प्रकार स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के लिए पीएफसी को चार नई लाइनें दी गई हैं जिसके लिए हमने एसपीवी सृजित कर दिए हैं और इनकी प्रक्रिया जारी है।

अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पुनर्गठित एपीडीआरपी योजना से संबंधित है, जिसके विवरण मैंने आप सभी को पहले से ही दिए हैं। हम बड़ी तेजी से इस योजना का कार्यान्वयन कर रहे हैं और अब तक लगभग 215

कस्बों को एकीकृत किया जा चुका है जो चार राज्यों में हानि को कम करने में सहायता कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं और तदनुसार मैं उनका समाधान करूंगा।

मॉडरेटर : धन्यवाद। देवियो और सज्जनो, अब हम प्रश्नोत्तर सत्र की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न बैंक ऑफ अमेरिका से श्री विकास गांधी की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

विकेश गांधी : महोदय, सुप्रभात। मेरे केवल दो प्रश्न हैं। एक इस संधिकालीन वित्त पोषण से संबंधित है जो आपने 19000 करोड़ रूपए के रूप में स्वीकृत किया था और मेरा विश्वास है कि आपने अब तक 5500 करोड़ रूपए का संवितरण किया है। वे दरें क्या होंगी जिन पर आप इन राज्यों से जटिल रूप से, औसतन प्रभारित करेंगे?

सतनाम सिंह: ठीक है। सामान्य दर हमारे मूल्यांकन में वर्गीकृत किए अनुसार व्यवस्था पर निर्भर करती है। यह सामान्य दरों के रूप में 12.5% से 12.75% अथवा 13% की रेंज में हो सकती है।

विकेश गांधी : दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आप मुझे इस बात की कुछ जानकारी देंगे कि इस राजकोषीय वर्ष की दूसरी छमाही और आगामी वर्ष में आपकी कितनी परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्य निर्धारण किया जा रहा है और इसी तारतम्य में आपका ऋण कितना है?

सतनाम सिंह: वर्ष 2012-13 की बकाया अवधि में परिसंपत्तियों का कुल पुनर्मूल्य निर्धारण लगभग 19,286 करोड़ रूपए है और वित्त वर्ष 2013-14 में

यह लगभग 26,093 करोड़ रूपए है। इसी प्रकार वित्त वर्ष 2012-13 की दूसरी छमाही में देनदारी लगभग 23,656 करोड़ रूपए और वर्ष 2013-14 में 4,283 करोड़ रूपए है।

सुनील कुमार : महज इस बात की जानकारी दें कि ठीक अभी आपका टीयर-I अंतिम रूप से क्या होगा?

सतनाम सिंह: 30.9.2012 की स्थिति के अनुसार हमारी टीयर-I पूंजी 21,450 करोड़ रूपए है।

विकेश गांधी: श्रीमाजी, मैं समझता हूं कि आपने इस 1200 करोड़ रूपए के प्रावधान का एक बफर स्टॉक दिया है, परंतु क्या ऐसी कोई आवश्यकता है कि आप इस राशि को टीयर-। के भाग के रूप में शामिल नहीं कर रहे हैं या यह केवल प्रबंधन का निर्णय है कि इसे शामिल न किया जाए?

सतनाम सिंह: यह हमारा निर्णय नहीं है, यह उन दिशा निर्देशों पर आधारित है, जिनका हमने अनुपालन किया है और जिनके अनुसार इसे वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इस आशय के संदर्भ में हमें भारतीय रिजर्व बैंक से वर्गीकरण हेतु निदेश प्राप्त हुए हैं। यह हमारा निर्णय नहीं है। हम आपको स्पष्टीकरण देते हैं कि यह आरक्षित राशि किससे संबंधित है। हमारी कंपनी धारा 4क के अंतर्गत आने वाली कंपनी है और इसके परिणामस्वरूप यदि हम अपनी निवल दीर्घकालीन आय की 5% राशि इस आरक्षित निधि में लेते हैं तो उस सीमा तक इसमें कर संबंधी छूट प्राप्त होती है। इसीलिए हम समय समय पर हर वर्ष इस आरक्षित निधि

का सृजन करते रहे हैं, परंतु हमने इस आरक्षित निधि का सदुपयोग कभी भी नहीं किया है क्योंकि हमने पिछले 26 वर्ष में अथवा हमारी कंपनी की स्थापना से अभी तक किसी भी अशोध्य ऋण को कभी भी बट्टे खाते में नहीं डाला है। वास्तविक रूप से हमें इसके लिए रोक दिया गया है।

विकेश गांधी: इसका आशय यह है कि जिन 8 आधारभूत बिंदुओं की आप चर्चा कर रहे हैं और जो आगामी तीन वर्ष में बनाए जाने हैं, को भी इसी तरह तैयार किया जाएगा अथवा इसे अलग ढंग से बनाया जाएगा?

सतनाम सिंह: हम भविष्य में जो कुछ भी सृजित करेंगे? क्या आप अपना प्रश्न दोहरा सकते हैं?

विकेश गांधी: मैं केवल यह कह रहा था कि आगामी तीन वर्ष के लिए एक मानक परिसंपत्ति प्रावधान के रूप में आप जिस 0.08% की चर्चा कर रहे हैं, क्या यह भी इसी फोल्ड में शामिल होगा अथवा यह आपके तुलन पत्र के परिप्रेक्ष्य में एक अलग आइटम के रूप में दर्शाया जाएगा?

सतनाम सिंह: यह अलग मद होगा, परंतु टीयर-II में शामिल होगा क्योंकि यह आरक्षित निधि का भाग नहीं जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य है, वह 0.08% उसका भाग नहीं है। इसलिए हमें इसे अलग से दर्शाना पड़ेगा।

विकेश गांधी: बहुत अच्छा। आपका धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं

मॉडरेटर: आपका धन्यवाद। अगला प्रश्न इक्वेरस सिक्योरिटीज से देवम मोदी की

लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

देवम मोदी: महोदय, नमस्कार। मुख्य रूप से हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसी कुछ विशेष परिसंपत्तियां हैं, जिनके बारे में यह खबर है कि उनसे चूक हुई है, उनमें सुजलोन शामिल है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि क्या यह हमारे पोर्टफोलियो में शामिल है और यह किस प्रकार उसकी भरपाई कर रही है?

सतनाम सिंह: हम सुजलोन को दो वर्ष पहले कुछ धनराशि उधार दी थी, लेकिन यह कार्यकारी पूंजी का भाग नहीं थी, जो उन्होंने अन्य बैंकों से ऋण के रूप में ली थी। हमने उन्हें यह ऋण पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विनिर्माण हेतु किए जाने वाले उनके पूंजीगत व्यय के लिए दी थी। दिए गए ऋण की कुल राशि लगभग 934 करोड़ रूपए है और इस प्रकार अभी कुछ बकाया भुगतान हैं, परंतु हम लगातार उनके संपर्क में हैं और उन्होंने नवंबर के अंत तक अथवा उसके आस पास उसके भुगतान का वादा किया है, परंतु अब हमें देखना है कि आगे क्या परिस्थितियां निर्मित होती हैं।

देवम मोदी: महोदय, एनपीए की सूची में दर्शायी गई विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में यदि हम इन्हें मानक पूंजी के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति नहीं लेते हैं तो वित्त वर्ष 2013 एवं वित्त वर्ष 2014 में कितनी धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी?

सतनाम सिंह: नहीं, वर्तमान में हमारी एनपीए सूची में तीन प्रमुख परियोजनाएं शामिल

हैं। दो और छोटी परियोजनाएं भी इसमें शामिल हैं। ये परियोजनाएं कोनासीमा गैस परियोजना, महेश्वर जल विद्युत परियोजना और आर.एस. इण्डिया पवन ऊर्जा परियोजना हैं। जहां तक इन परियोजनाओं को एनपीए के अंतर्गत वर्गीकृत करने का संबंध है तो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से अब अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोनासीमा गैस परियोजना एनपीए के अंतर्गत शामिल हो गई है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध नहीं है अन्यथा परियोजना बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आर.एस. इण्डिया पवन ऊर्जा परियोजना एनपीए में शामिल हो गई क्योंकि स्थापना में विलंब होने के कारण इसका पुनर्भुगतान ऑफ पीक राजस्व अवधि में आ गया है। ये दोनों परियोजनाएं अर्थात कोनासीमा गैस परियोजना और आर. एस. इण्डिया में से यदि कोनासीमा गैस परियोजना के लिए गैस प्राप्त होने लगती है तो हम इनका पुनर्गठन कर समायोजन करने का प्रयास करेंगे ताकि इनका पुनर्भुगतान ऑफ पीक राजस्व अवधि में न आ सके, बल्कि पीक राजस्व अवधि के प्रारंभ में किया जाए। इस प्रकार दोनों परियोजनाओं के कुछ समय पश्चात एनपीए स्तर से बाहर आने की संभावना है। इस प्रक्रिया में आर.एस. इण्डिया पहली परियोजना होगी। मेरा मानना है कि चौथी तिमाही में यह एनपीए के अंतर्गत शामिल नहीं होगी। परंतु गैस परियोजना के संबंध में मेरे लिए यह कह पाना कठिन होगा कि सरकार गैस की उपलब्धता के लिए कब तक संभावना सृजित करेगी। तीसरी परियोजना, जो वर्तमान में एनपीए श्रेणी के अंतर्गत आती है, वह श्री

महेश्वर जल विद्युत परियोजना है, जो प्राथमिक रूप से एनपीए श्रेणी में इसलिए चली गई है क्योंकि इसका प्रमोटर आवश्यक इक्विटी निवेश करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि परियोजना स्थापना की दृष्टि से तैयार है; इसकी 10 यूनिटों में से कम 3 यूनिटें तीन से छः माह की अवधि में स्थापना के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि इनके लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराई जाए। हम मध्य प्रदेश की सरकार और प्रमोटर दोनों के संपर्क में हैं और हम इस बात की संभावनाएं तैयार कर रहे हैं कि या तो मध्य प्रदेश सरकार इस परियोजना में इक्विटी निवेश करे या फिर प्रोमोटर ही कहीं से इक्विटी की व्यवस्था करे, ताकि परियोजना राजस्व सृजित करना प्रारंभ कर दे। यदि एक बार परियोजनाएं राजस्व सृजित करने लगती हैं, तो ये समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं, परंतु हमें इन परियोजनाओं को मानक परिसंपत्तियों के रूप में अथवा अन्यथा वर्गीकृत करने या उन्हें मानक परिसंपत्तियों के रूप में पुन:वर्गीकृत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से कोई अनुमति प्राप्त नहीं हुई है।

देवम मोदी: हमारे पोर्टफोलियो में परिसंपत्तियों के कमतर विकास की तुलना में प्रचालनरत परिसंपत्तियों का क्या अनुपात होगा?

सतनाम सिंह: उत्पादन के क्षेत्र में हमारी परिसंपत्तियों का लगभग 35% भाग ऐसी परियोजनाओं के लिए जिनकी स्थापना पहले ही कर दी गई है। उत्पादन क्षेत्र में बकाया परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं।

देवम मोदी: महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न केवल यही था।

मॉडरेटर: धन्यवाद। अगला प्रश्न एडेलवीज से श्री कुनाल शाह की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

कुनाल शाह: अच्छी संख्या के लिए बधाई। श्रीमान जी मैं केवल कंपनी की स्वीकृतियों और संवितरण का जायजा लेना चाहता हूं। हमने पिछली बार 40,000 करोड़ रूपए के अपने संवितरण और 45,150 करोड़ रूपए की स्वीकृतियों के संबंध में जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, वे डिस्कॉम को संधिकालीन वित्त पोषण को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे या हम उनमें संशोधन करने वाले हैं और हम संगत रूप से उन्हें अधिक मानते हैं क्योंकि 41,732 करोड़ रूपए की राशि हमने पहली छमाही के दौरान ही स्वीकृत कर दी है?

सतनाम सिंह: यह आंकड़ा उस समय था क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि हमें संधिकालीन वित्त पोषण करना होगा। इसलिए वे आंकड़े संधिकालीन वित्त में शामिल नहीं हैं, परंतु चूंकि आपने पहले से ही स्वीकृत कर दिया है अत: इसे हमारे लक्ष्यों के बजाय हमारी उपलब्धियों में शामिल किया जाएगा।

कुनाल शाह: महोदय, क्या हम इस पूरे 19000 करोड़ रूपए की राशि के इस वित्त वर्ष की समाप्ति तक संवितरित किए जाने की अपेक्षा करें?

सतनाम सिंह: हमने इस पर कड़ी शर्तें लागू की हैं। इस प्रकार यदि सभी छ: राज्य इन सभी शर्तों का अनुपालन करने में सक्षम होते हैं, तो हां, परंतु यदि इन राज्यों में से कुछ राज्य इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो नहीं। उदाहरण के लिए हमने उस समय लगभग 50% की बात कही है जब वर्तमान वर्ष का टैरिफ लागू है और अन्य 20% की बात तब कही जा

सकती है जब मूल्य ईंधन मूल्य समायोजन स्वचालित ढंग से किया गया है। कुछ राज्यों ने यहां तक कि टैरिफ संशोधित किए जाने के बावजूद भी ईंधन मूल्य समायोजन स्वचालित ढंग से अभी भी नहीं किया है। इस प्रकार यह विभिन्न निर्णयों के परिणामस्वरूप अतिरिक्त राजस्व सृजित करने में वितरण कंपनियों के कीर्तिमानों से संबद्ध है। इस प्रकार यदि वे ऐसे निर्णय लेते हैं, तो हां, परंतु यदि अन्यथा कोई निर्णय लिया जाता है, तो नहीं।

कुनाल शाह: महोदय, इस 5500 करोड़ रूपए की राशि आज की तारीख तक इन छ: राज्यों में से कितने राज्यों को प्रदान की गई है?

सतनाम सिंह: मेरा मानना है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे चार राज्यों को आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों को कोई संवितरण नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में कोई भी स्वीकृति नहीं की गई है न ही पंजाब को हमने कोई स्वीकृति दी है, परंतु उन्होंने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

कुनाल शाह: महोदय, तो इन चार राज्यों में ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इन शर्तों को पूरा किया है, इस प्रकार संधिकालीन वित्त पोषण अथवा इस संबंध में की गई स्वीकृतियों के संदर्भ में बकाया कोई भी राशि, यदि देय है, तो उसका संवितरण वित्त वर्ष 2013 में किया जाएगा। क्या यह निष्पक्ष लगाया गया अनुमान होगा अथवा इस संबंध में कुछ नई शर्तें लागू होंगी, जिनका अनुपालन करना आवश्यक होगा?

सतनाम सिंह: कुछ शर्तों का अनुपालन किया जाना अभी शेष है। अन्यथा वे अब तक पूर्ण संवितरण करने में सक्षम हो गए होते।

कुनाल शाह: महोदय, यह भी मील के पत्थर जैसा हुआ होता, कोई भी शर्तें क्यों न हों, उनका पालन किया जाता है, हम उनका पालन करेंगे। महोदय, इस संबंध में आपका मूल्यांकन क्या है, इस राजकोषीय वर्ष की समाप्ति तक इसमें से कितनी राशि का संवितरण हो जाएगा?

सतनाम सिंह: इस राजकोषीय वर्ष के अंत तक अधिकांश संवितरण हो जाएगा। वास्तविक रूप से विद्युत मंत्रालय स्वयं भी वित्तीय पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। वस्तुत: सचिव, विद्युत मंत्रालय ने शनिवार को सात राज्यों की एक बैठक आयोजित की जहां राज्य के प्रतिनिधियों से इस बात पर चर्चा की गई कि कब तक और किस तरीके से ये राज्य आगे बढ़ेंगे और वित्तीय पुनर्गठन योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

कुनाल शाह: महोदय, इस संधिकालीन वित्त पोषण के पश्चात ऋण वृद्धि और संवितरण वृद्धि के संबंध में आपकी क्या अपेक्षा है?

सतनाम सिंह: मुझे विश्वास है कि आप यह जानते हैं कि मुझे इस संबंध में कोई मार्ग दर्शन देने का अधिकार नहीं है, परंतु हम लगभग 25% की अपनी सामान्य वृद्धि दर बनाए रखने में सफल होंगे। यह 20% से 25% की रेंज में रहेगी।

कुनाल शाह: मैं इस संबंध में केवल अद्यतन स्थिति की जानकारी चाहता हूं। पिछली बार आपने आस्ट्रेलिया की जीवीके कोल माइंस को लगभग 135 मिलियन डॉलर की राशि स्वीकृति करने के संदर्भ में कुछ बातों का उल्लेख किया था। अत: इस संबंध में कुछ प्रकाश डालें कि यह क्या माजरा था? आपने वर्धा पावर और एसआर पावर के साथ भी कुछ समस्याओं का जिक्र किया था। अत: इस संबंध में अब आपका क्या मत है?

सतनाम सिंह: जीवीके को हमने अभी तक कोई स्वीकृति नहीं दी है। हमने वास्तविक रूप से इस मामले को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया है। इसका आशय यह है कि उन्होंने अभी तक इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि हम इस प्रकार का लेनदेन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं अथवा नहीं। हमने उस निर्णय को स्थगित कर दिया है। वीडियोकॉन के संबंध में मैंने पहले ही अपने आरंभिक वक्तव्य में आपको जानकारी दी

है कि हम उसके साथ मोजाम्बिक और अन्य देशों में गैस फील्ड के लिए लेनदेन कर रहे हैं। हमने 2200 करोड़ रूपए का पहले ही स्वीकृत कर दिया है। परंतु जहां तक एस्सार महान और वर्धा परियोजनाओं का संबंध हैं, तो इनके मामले को देश के सर्वोच्च प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया है और आशा है कि इन परियोजनाओं की स्थापना से पहले ईंधन संबंधी मुद्दों को हल कर लिया जाएगा।

कुनाल शाह: महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।

मॉडरेटर: धन्यवाद।

उमंग शाह: यहां मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा, महोदय, परिसंपत्तियों की गुणवत्ता पर हमारे दृष्टिकोण के संदर्भ में एक प्रश्न, जैसा आपने उल्लेख किया है कि परिसंपत्ति की गुणवत्ता के संबंध में आपको कोई महत्वपूर्ण जोखिम दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु मेरा मुख्य प्रश्न निजी क्षेत्र के एक्सपोजर से संबंधित है जो मोटे तौर पर हमारी ऋण बही के लगभग 12% के बराबर है। इस प्रकार बढ़ रहे जोखिम को ध्यान में रखते हुए और जो हम बड़े विकासकर्ताओं जैसे लैंको, सुजलोन के बारे में दिन प्रतिदिन मीडिया में छपने वाले लेखों में पढ़ते हैं, को ध्यान में रखते हुए परिसंपत्ति गुणवत्ता के संदर्भ में हमारा दृष्टिकोण मुख्य रूप से ऐसे निजी क्षेत्र से संबंधित है जो लगातार आगे बढ़ रहा है?

सतनाम सिंह: यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कि कोई उत्पादन स्टेशन राज्य क्षेत्र में है अथवा निजी क्षेत्र में। उनमें से सभी अथवा ज्यादातर अपने उत्पाद की बिक्री वितरण कंपनियों को कर रही हैं और वितरण कंपनियों की माली हालत में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा मैं आपके साथ पहले भी कर चुका हूं। इस प्रकार इन विकासकर्ताओं के समक्ष परेशानी केवल इस बात को लेकर है क्योंकि वितरण कंपनियां उनका भुगतान नहीं कर रही हैं। इस पुनर्गठन योजना के कार्यान्वित हो जाने और पावर फाइनेंस कारपोरेशन से संधिकालीन वित्त पोषण की शर्तों का भी पूरी तरह से कार्यान्वयन हो जाने के पश्चात जहां तक कि गैर निष्पादन

परिसंपत्तियों का संबंध है, तो उनको लेकर कोई समस्या नहीं रहेगी। मैंने आपके साथ पहले ही चर्चा की है कि हमने संधिकालीन ऋण का संवितरण पहले से ही शुरू कर दिया है; इसका कुछ हिस्सा संवितरित कर दिया गया है। इस प्रकार यह उनकी काफी सहायता कर रहा है।

उमंग शाह: महोदय, मैं सिर्फ आंकड़ों की जानकारी चाहता हूं। क्या हमने तिमाही के दौरान किसी ऋण का पुनर्गठन किया है या उसे पुन: अनुसूचित किया है और हमारी खाता बही में बकाया पुनर्गठित कुल ऋण कितना होगा?

सतनाम सिंह: चूंकि हमारा ऋण परियोजना विशेष पर आधारित है, अत: ऋण के पुनर्गठन का तब तक कोई प्रश्न नहीं उठता है जब तक कि कोई प्राकृतिक आपदा घटित न हो। मुझे विश्वास है कि आपको इस बात की जानकारी होगी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने उस समय अपने ऋणों का पुनर्गठन किया था जब गुजरात में भूकंप आया था, तमिलनाडु में सुनामी आई थी और उड़ीसा में तूफानी वर्षा हुई थी। इस प्रकार हम अन्य परिस्थितियों में पुनर्गठन को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस प्रकार इन तीन राज्यों से संबंधित आंकड़े हमारी बही में लगभग 3096 करोड़ रूपए के रूपए में हैं, जिनका पुनर्गठन काफी पहले किया गया था न कि अभी हाल ही के वर्षों में।

उमंग शाह: महोदय, बस केवल अंतिम बात। लैंको समूह को हमारा एक्सपोजर क्या होगा?

सतनाम सिंह: यह 5000 करोड़ रूपए से थोड़ा कम है।

उमंग शाह: 5000 करोड़ रूपए से थोड़ा कम, परंतु इसमें गैर निधि आधारित एक्सपोजर भी शामिल है?

सतनाम सिंह: मुझे ऐसा नहीं लगता है। हमने उन्हें कोई भी गैर निधि आधारित सुविधा नहीं दी है, परंतु 5000 करोड़ रूपए का यह एक्सपोजर जिसकी मैंने चर्चा की है, इसमें हमारे द्वारा की गई स्वीकृतियां शामिल हो सकती हैं परंतु

अभी तक कोई संवितरण नहीं किया गया है। इस प्रकार यह भी आप केवल इस बात की जानकारी चाह रहे हैं कि कितना संवितरण किया गया है, तो यह लगभग 3052 करोड़ रूपए है।

उमंग शाह: महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरी ओर से इतना ही।

मॉडरेटर: धन्यवाद। अगला प्रश्न ड्यूच बैंक से श्री मनीष शुक्ला की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

मनीष शुक्ला : महोदय, सुप्रभात। मैं एक बार फिर प्रावधानों की चर्चा करना चाहूंगा, आप अपनी आरक्षित निधियों में लगातार प्रावधान कर राशि संचित कर रहे हैं, जैसा कि वर्तमान में भी आप राशि संचित कर रहे हैं और इसके अलावा आप प्रावधानों के आठ मुख्य बिन्दु तैयार करेंगे। क्या यह सही है?

सतनाम सिंह: हां, यह सही है।

मनीष शुक्ला: उत्तरोत्तर ऋण जो आप आगे से वितरित करेंगे कि उत्तरोत्तर स्थिति क्या है? क्या आप 25 अपफ्रंट तैयार करेंगे अथवा वह भी प्रावधानों के रूप में ही होगा?

सतनाम सिंह: किन्हीं भी परिसंपत्तियों पर 0.08 आधार पर और जब हम 0.25 के स्तर तक पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रति वर्ष 0.25 स्तर तक।

मनीष शुक्ला: इस प्रकार राजकोषीय वर्ष 2015 तक यह नई तथा पुरानी दोनों परियोजनाओं के लिए सम्मिलित रूप से 0.08 हो जाएगा?

सतनाम सिंह: हां, यह सही है।

मनीष शुक्ला: हमारी ओर से इतना ही। धन्यवाद।

मॉडरेटर: धन्यवाद। अगला प्रश्न क्वैंटम परिसंपत्ति प्रबंधन से निकिता गोदवानी की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

अतुल: मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आपने ऊर्जा क्षेत्र को कुछ स्वीकृतियां दी थीं। बकाया स्वीकृतियां कितनी होंगी और अब तक कितना संवितरण किया गया है?

सतनाम सिंह: आपने ऊर्जा क्षेत्र की बात कही, तो उसका क्या आशय है?

अतुल: मेरा मानना है कि आपने यह कहा था कि आप व्यापक तौर पर कोल माइन क्षेत्र और ऑयल फील्ड सेक्टर में प्रवेश करेंगे, मुझे स्मरण है कि इसकी चर्चा वार्षिक विश्लेषक बैठक के दौरान की गई थी?

सतनाम सिंह: हमने वीडियोकॉन को 2200 करोड़ रूपए स्वीकृत किए हैं, परंतु अभी तक कोई संवितरण नहीं किया गया है और अन्य कंपनी जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वह जीवीके थी जहां हमने अभी तक कोई स्वीकृति नहीं दी है। इस प्रकार केवल 2200 करोड़ रूपए है, परंतु कोई संवितरण नहीं किया गया।

अतुल: मेरा अन्य प्रश्न जैसा आपने चर्चा की है, सुजलोन से संबंधित है, संभवत: आपने इसे केपैक्स से संबद्ध किया है और बकाया राशि जैसा कि आपने उल्लेख किया है 934 करोड़ रूपए में इसे शामिल किया है जो निवल बकाया राशि है या इस संबंध में कोई पुनर्भुगतान किए गए थे और यह ऋण खाता किस प्रकार चल रहा है। क्या आप कुछ जानकारी दे सकते हैं?

सतनाम सिंह: कुल बकाया ऋण 934 करोड़ रूपए है, परंतु यदि आप सितंबर की स्थिति के अनुसार भुगतान के बारे में जानना चाहते हैं तो यह लगभग 47 करोड़ रूपए था।

अतुल: मेरा मानना है कि अन्य बैंक इस विशेष खाते का पुनर्गठन करने वाले हैं क्योंकि हमारा मानना है कि यह समूह बुरे दौर से गुजर रहा है अर्थात

इसके समक्ष कुछ परेशानियां हैं। आप एनपीए के संबंध में क्या उपाय करेंगे अथवा आप इस विशेष मुद्दे के संबंध में क्या सोच रहे हैं?

सतनाम सिंह: यह अभी तक एनपीए श्रेणी में नहीं आया है और जैसा कि मैंने आपके साथ चर्चा की है कि हम उस कार्यकारी पूंजी का हिस्सा नहीं हैं। इसलिए हमारा केपैक्स व्यय अलग है। यह परियोजना विशेष पर आधारित ऋण है। यह अलग मामला है, परंतु वे ऋण का भुगतान समय पर नहीं कर पाए हैं। परंतु यह हमारी बही में एक मानक परिसंपत्ति है और जहां तक कि इस ऋण का संबंध है तो उनकी ओर से इसके पुनर्गठन के लिए हमारे पास अभी तक कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

अतुल: धन्यवाद।

मॉडरेटर: धन्यवाद। अगला प्रश्न इक्विरेश सिक्योरिटीज से देवन मोदी की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

देवन मोदी : मैं केवल 0.08% के प्रावधान को समझना चाहता हूं इस प्रकार उसका आशय यह है कि मैं केवल इस संबंध में स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगली तिमाही से परिसंपत्तियों पर संपूर्ण लंबित ऋणों का प्रावधान देखने को मिलेगा, क्या आप प्रत्येक तिमाही में 0.08% का प्रावधान करेंगे, क्या यह सही है?

सतनाम सिंह: हां, इस वर्ष के लिए क्योंकि हमने अभी हाल ही में निर्णय लिया है, मैंने पहली तीन तिमाही की बात कही है, हम तीसरी तिमाही में प्रावधान करेंगे क्योंकि हमने अभी हाल ही में इस संबंध में निर्णय लिया है। पूरे वर्ष के लिए यह 0.08% होगा। इस प्रकार यदि आप तीसरी तिमाही में आनुपातिक रूप से देखेंगे तो यह 0.06% के आस पास होगा।

देवन मोदी : बहुत बहुत धन्यवाद।

मॉडरेटर: धन्यवाद। अगला प्रश्न दाइवा से पुनीत श्रीवास्तव की लाइन से है।

कृपया अपनी बात कहें।

पुनीत श्रीवास्तव: महोदय, सुप्रभात। मेरा प्रश्न गैस आधारित परियोजनाओं से संबंधित है। मुख्य रूप से मैं केवल इस बात का ब्यौरा जानना चाहता हूं कि बकाया एक्सपोजर कितना है और स्वीकृत राशि कितनी है। साथ ही इस बात निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का ब्रेकअप चाहता हूं?

सतनाम सिंह: आप इस आशय के लिए कोई ईमेल क्यों नहीं भेज देते। मेरे पास अभी तैयार स्थिति में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, परंतु ये आंकड़े एकत्र करने में कुछ सेकंड ही लगेंगे। हमें एक ईमेल भेज दें और हम उसका जवाब दे देंगे।

पुनीत श्रीवास्तव: क्या आप कम से कम गैस आधारित परियोजना पर कुल कुल एक्सपोजर की जानकारी दे सकते हैं?

सतनाम सिंह: यह लगभग 7810 करोड़ रूपए है।

पुनीत श्रीवास्तव: धन्यवाद।

मॉडरेटर: धन्यवाद। चूंकि अब हमारे पास कोई अगला प्रश्न नहीं है, अत: मैं सभा की आगामी कार्रवाई के समापन हेतु श्री उमंग शाह को आमंत्रित करना चाहूंगा जो आएं और अपना धन्यवाद ज्ञापन करें। कृपया आगे आएं।

उमंग शाह: धन्यवाद मेलिसा। मैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की ओर से श्री सतनाम सिंह और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शीर्षस्थ प्रबंधन को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमें इस कॉल के आयोजन का अवसर प्रदान किया और हम उन सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने इसमें भाग लिया। श्री सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी प्रतिभागियों को भी एक बार पुन: धन्यवाद।

सतनाम सिंह: बहुत बहुत धन्यवाद।

मॉडरेटर: धन्यवाद। देवियो और सज्जनो, आज की कॉन्फ्रेंस कॉल यहीं समाप्त होती है। हमारे बीच उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। अब आप लाइनें डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। पुन: धन्यवाद ।